International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in November 2024, ISSN -2393-8048

भारत-नेपाल संबंधों का वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियां: 2014 से अद्यतन

मयंक सिंह, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ रजनीकान्त पाण्डेय, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

शोध सार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 3-4 अगस्त, 2014 तक की गई नेपाल की दो दिवसीय यात्रा ने भारत-नेपाल संबंधों में एक नई शुरुआत की नींव रख दी है। प्रधानमंत्री ने नेपाल के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का वायदा किया। इसके अलावा संप्रभुता पर बल प्रदान करने तथा नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने नेपाल की जनता के हृदयों और मस्तिष्कों को जीतने का सफल प्रयास किया और भारत की छवि को एक प्रधान शक्ति के रूप में एक निश्चित सीमा तक ही सीमित रखने का उल्लेख किया।

बीज शब्द: नेपाल, भारत, व्यापार सहयोग, कालापानी, सूचना प्रौद्योगिकी।

प्रस्तावना

विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक पांचवा स्थान रखता है तथा तथा एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक रूप से मैत्री पूर्ण रहे हैं लेकिन विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कभी-कभी ऐसा लगता है कि दोनों असहज सहयोगी के रूप में अपने-अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। हालाकि दोनों देश सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब पाते हैं भारत स्वाधीनता के बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करता है। वहीं नेपाल ऐतिहासिक रूप से राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार करता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विशेषताओं के कारण भारत की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव नेपाल पर पड़ा और वहां भी 1990 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई। ऐसी स्थिति में नेपाल को भारत के लोकतांत्रिक राष्ट्रों से निकली समृद्धि का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जबकि भारत नेपाल के संबंध गहरे और व्यापक हैं, काठमांडू को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह जलविद्युत और पर्यटन सहयोग के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों के माध्यम से इन संभावित लाभों को प्राप्त कर सके। नेपाल प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को नरेंद्र मोदी के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध विकसित करना चाहिए, न केवल द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए, बल्कि अपनी "पड़ोसी पहले नीति के सार को साकार करने के लिए भी।

नेपाल भारत के पांच राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत आपसी संबंधों से स्पष्ट होते हैं। नेपाल भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत एक प्राथमिकता वाला साझेदार है।

गत दशकों में नेपाल के साथ भारत के रिश्तों में उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिले हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर 'पडोसियों को प्राथमिकता देने की नीति की चर्चा करते रहे हैं। मई 2014 में पहली बार सत्ता संभालने के बाद मोदी ने अगस्त के महीने में नेपाल की बेहद कामयाब यात्रा की थी। हालाकि, 2016 में दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। उस समय पहले तो भारत पर नेपाली संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में दखलंदाजी करने के इल्जाम लगाए गए। उसके बाद भारत पर 'अनाधिकारिक चक्काजाम का भी दोष मढ़ा गया। इससे नेपाल में भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोष देखने को मिला। इससे ये विचार और पुख्ता होकर सामने आया कि नेपाली राष्ट्रवाद और भारत विरोधी विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

भारत और नेपाल के बीच अविश्वास की इस बढ़ती खाई के पीछे, नेपाल के घरेलू मामलों में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को जिम्मेदार बताया जा रहा है। चीन दशकों से नेपाल के वामपंथियों को समर्थन दे रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के साथ, चीन का नेपाल की अंदरूनी राजनीति में दखल शीर्ष पर पहुंच गया था। नेपाल के चीन के प्रति बढ़ते झुकाव की इस सोच को तब और बढ़ावा मिला, जब 2015 में नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत ने नेपाल की सीमा की नाकेबंदी कर दी थी।,

नेपाल के अंदरूनी मामलों में चीन के बढ़ते दखल को लेकर भारत की चिंताएं तब और सही साबित हुई थी, जब चीन ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में अंदरूनी संघर्ष में सीधे दखल देते हुए सत्ताधारी पार्टी को विभाजन से बचाया था। भारत के कुछ कदमों को एकतरफा ठहराते हुए, नेपाल ने भारत के खिलाफ अपने रवैये को और सख्त कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति का ये कहते हुए मखौल उड़ाया था कि, 'क्या ये सत्यमेव जयते नहीं सीमामेव जयते हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच सकारात्मक संवाद की रही सही संभावनाएं भी समाप्त हो गई थी।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से 3 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर थे। लंबे समय से इस दौरे का इंतजार हो रहा था। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देउबा की ये पहली द्विपक्षीय स्तर की विदेश यात्रा स्थापित परंपराओं के मुताबिक रही। भले ही इस दौरे के नतीजे सामान्य दिखाई दें, लेकिन अहम् बात ये है कि भारत और नेपाल दोनों ही विभाजनकारी मुद्दों को अलग रखने में कामयाब रहे। 75 साल के देउबा राजनीति के पुराने धुरंधर है। 1995 में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने देउबा का ये पांचवां कार्यकाल थे। वो दोनों देशों के बीच के रिश्तों की पेचीदगियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे।

प्रधानमंत्री देउबा के दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 35 किमी लंबे रेल संपर्क का चालू होना रहा। आगे के दो चरणों में इसका बीजलपुरा से बरदिबास तक विस्तार हो जाएगा। 787 करोड़ रु. की लागत वाली ये परियोजना एक साल से तैयार थी। दरअसल नेपाल में स्टाफ की भर्तियों के लिए कंपनी स्थापित करने से जुड़ी आवश्यक प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने की वजह से इसे चालू करने का काम अटका हुआ था। शुरुआती दौर में कोकण रेलवे कॉरपोरेशन इसके लिए जरूरी तकनीकी मदद मुहैया कराएगा। दूसरी परियोजना के तौर पर 90 किमी लंबी 132 किलोवाट की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन किया गया। ये ट्रांसमिशन लाइन टिला (सोलूखुंबू) से भारतीय सीमा के नजदीक

International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in November 2024, ISSN -2393-8048

मिरचीया (सिराहा) को जोड़ती है। इसे एक्सिस बैंक द्वारा 200 करोड़ रु. के रियायती कर्ज की मदद से तैयार किया गया है। इसके तहत सोलू कॉरिडोर में दर्जनभर पनबिजली परियोजनाएं तैयार करने की योजना है। इस सिलसिले में नेपाल बिजली प्राधिकरण 325 मेगावाट के बिजली खरीद समझौते पूरे कर चुका है। इनके अलावा रेलवे सेक्टर में तकनीकी सहयोग मुहैया कराने से जुड़ा समझौता भी हुआ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल के दाखिले पर भी सहमति बनी है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौते पर भी दस्तखत हुए है।

पिछले सालों में नेपाल-भारत के रिश्ते में कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों देश के सम्बन्ध अपनी बुलंदी पर हैं। 17 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री का नेपाल आना नेपाल-भारत के मजबूत सम्बन्ध को सिद्ध करता है। नेपाल किस तरह भारत की मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में रहा, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल को आमंत्रित किया गया था। नेपाल-भारत रिश्तो की अहमियत इस वजह से भी ज्यादा है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले पड़ोस की नीति के मद्देनजर नेपाल उनके शुरूआती विदेशी दौरों में से एक था, जबकि इससे पहले आखिरी बार 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। हालांकि, 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेपाल की यात्रा की थी, लेकिन वह यात्रा द्विपक्षीय नहीं थी बल्कि सार्क देशों का शिखर सम्मेलन था। नेपाल के भूकंप में राहत का अद्भुत उदाहरण है, जब 27 अप्रैल, 2015 को नेपाल की धरती में हलचल हुई और आठ हजार से ज्यादा जानें एक साथ काल के गाल में समा गई एवं जान के साथ अरबों रूपये की संपत्ति का नुकसान हुआ, हलचल नेपाल में हुई लेकिन दर्द भारत को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई और नेपाल के लिए भारत की मदद के द्वार खोल दिए। नेपाल में जिस तेजी से मदद पहुंचाई गई वो अद्भुत था। भारतीय आपदा प्रबंधन की टीम ने हजारों जानें बचाई। सबसे खास रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय का नेपाल सरकार से बेहतरीन समन्वय रहा। मानवीय सहायता और आपदा राहत में भारत ने नेपाल में भूकंप पुनर्निमाण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल टीम एवं बचाव व राहत सामग्री भेजी तथा 65 मिलियन अमरीकी डॉलर के नए लाइन क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल की पूरे विश्व ने सराहना की।

नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विशाखापटनम पोर्ट से नेपाल के कार्यों को जोड़ा गया। कोलकाता और हल्दिया में क्लियरिंग के झंझट से मुक्ति मिली और भारत-नेपाल सीमा पर ही इसकी प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था हो रही है। भारतीय होटल कंपनी ओयो ने घोषणा की कि वह नेपाल में निवेश करेगी। इसके लिए ओयो ने 2000 मिलियन डॉलर एयरबीएनबी कंपनी से उठाये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सहित तीन बैंकों ने नेपाल के विशालकाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 6800 करोड़ का कर्ज देने का वादा किया है। यह ऐलान नेपाल में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान किया गया। 100 मेगावाट के अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भारतीय कंपनी एसजेवीएन ने अपने अधिकार में ले लिया है। एसबीआई ने 6460 करोड़ रूपए, एवेरेस्ट बैंक ने 812. 61 करोड़ और नबील बैंक ने 487.98 करोड़ कर्ज देने की प्रतिबद्धता

दिखाई है। इस प्रोजेक्ट की नींव संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी और समकक्षी प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने रखी थी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1.04 अरब डॉलर है और यह पांच वर्षों की समयसीमा में पूर्ण होगा। यह प्रोजेक्ट प्रतिवर्ष 40187 मिलियन यूनिट्स बिजली का उत्पादन करेगा। यह भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त कार्य है। यह 21.9 फीसद बिजली नेपाल को मुफ्त में मुहैया करेगा। आंकड़ों के अनुसार यह प्रोजेक्ट नेपाल और भारत में 3000 नौकरियों का सृजन करेगा। भारत, जनकपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए नेपाल को 100 करोड़ रुपये देगा।

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 31 मई 2024 को चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। एक जून को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेपाल के पीएम ने द्विपक्षीय वार्ता की.. इस व्यापक बातचीत में हर उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिससे भविष्य में भारत-नेपाल संबंध और भी प्रगाढ़ हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत और नेपाल आपसी संबंधों को हिमालयी ऊंचाइयों पर ले जाने और सीमा मुद्दे समेत सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल साझेदारी को सुपरहिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे। इसी भावना के साथ हम सभी मुद्दों का समाधान करेंगे, चाहे वह सीमा से जुडा हो या कोई अन्य मुद्दा। बातचीत के बाद पीएम मोदी और प्रचंड ने साझा रूप से नेपाल के कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की एवं कुछ योजनाओं का उदघाटन भी किया गया और कुछ का शिलान्यास भी ।।

नेपाल में गठबंधन फेरबदल के बाद, नेपाल के विदेश मंत्री डॉ आरज़ू राणा देउबा की 18 से 22 अगस्त 2024 तक भारत की हालिया आधिकारिक यात्रा। भारत-नेपाल संबंधों के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करती है। यह यात्रा महत्वपूर्ण थी क्योंकि नेपाल अपने विश्वसनीय विकास साझेदार भारत से विकासात्मक समर्थन मांग रहा है और सहयोग के नए क्षितिज तलाश रहा है। भारत ने हमेशा नेपाल को एक मूल्यवान पड़ोसी माना है और 1950 के दशक की शुरुआत में नेपाल में आधुनिक विकास की शुरुआत से ही नेपाल को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की है।

नेपाली कांग्रेस (एनसी) और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी, जो 15 जुलाई 2024 को सत्ता में आई। बताया गया किविदेश मंत्री राणा की नई दिल्ली यात्रा को भारतीय अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण महत्व दिया गया था, जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारियों और प्रधान मंत्री मोदी ने डॉ राणा से मुलाकात की थी। नेपाली मीडिया ने बताया कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस स्तर का स्वागत "अप्रत्याशित" था। लेकिन बहुत स्वागत योग्य था। यह याद किया जा सकता है कि, अगस्त की शुरुआत में,भारत के नए विदेश सचिव की नेपाल की नियमित परिचय यात्रा के दौरान,

भारत ने नेपाल की नवगठित गठबंधन सरकार के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की थी।

हालांकि, हालिया उच्च स्तरीय यात्रा ने संकेत दिया कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का इच्छुक है और सहयोग के क्षितिज को व्यापक बनाने का इच्छुक है। इसके अलावा, पीएम ओली ने एक संतुलित विदेश नीति अपनाने की पुष्टि की है। हमें अपने पड़ोसियों को अपनी चिंताओं और स्थितियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराना होगा क्योंकि हम एक को दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करते हैं। हम एक अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं, बुरे नहीं।" उन्होंने आगे कहा कि "हम अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम भूराजनीति में चल रही अनिश्चितताओं के प्रति बहुत सचेत हैं। हम विश्व शांति के पक्ष में हैं और अपने नागरिकों की भलाई के प्रति संवेदनशील हैं।"

भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण विकास भागीदार होने के नाते, विकासात्मक समर्थन मांगने वाला सर्वोच्च प्राथमिकता वाला देश है। सबसे प्रमुख बात यह है कि विदेश मंत्री राणा की यात्रा ने नई दिल्ली का ध्यान जलविद्युत व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे पर आकर्षित किया, जिसमें एकीकृत चेक पोस्ट, सड़क और रेलवे संपर्क और बेहतर हवाई संपर्क शामिल हैं, और भारत के विभिन्न शहरों में अतिरिक्त मार्गों और सीधी उड़ानों का अनुरोध किया।

हालाँकि हाल ही में आधिकारिक यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल की अपेक्षित यात्रा से महत्वपूर्ण समझौते और प्रतिबद्धताएँ सामने आ सकती हैं जो वर्तमान नेपाली सरकार की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और विकास की खोज के साथ संरेखित हैं। इसके अलावा, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों पर चर्चा और समाधान करने का यह सही समय है, जिसने हाल के दिनों में नेपाली पक्ष की ओर से कई एकतरफा कदम उठाए हैं, खासकर प्रधानमंत्री ओली के पिछले कार्यकाल के दौरान। प्रधानमंत्री ओली ने हाल ही में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के संबंध में खुली बातचीत करने पर जोर दिया है। 7 सितंबर, 2024 को काठमांडू में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा कि "नेपाल और भारत के बीच बहुत कम समस्याएँ हैं, और अगर हम गर्मजोशी और खुली बातचीत बनाए रखें तो उन्हें हल किया जा सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि "साझा संसाधनों पर काम करते समय एकतरफा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यह आम सहमति और द्विपक्षीय चर्चा के आधार पर किया जाना चाहिए"

हाल ही में हुई उच्चस्तरीय यात्रा भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसमें विकास सहयोग की तलाश और सहयोग के दायरे का विस्तार करने की इच्छा पर विशेष जोर दिया गया है। नेपाल में नई सरकार के ये शुरुआती संकेत स्वागत योग्य हैं; हालाँकि इनका सुदृढ़ीकरण अभी देखा जाना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री ओली की ओर से डॉ. राणा द्वारा दिए गए नेपाल यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। हालाँकि, यात्रा की आधिकारिक तिथि की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

वर्तमान में भारत और नेपाल संबंधों में अनेक चुनौतियां विद्यमान है जिनमे से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है जिन्होंने भारत नेपाल सम्बन्ध को काफी हद तक जटिल बना दिया।

1. 2015 में भारत और नेपाल के संबंधों में दरार आ गई, जब भारत को पहली बार नेपाल में संविधान के मसौदे में हस्तक्षेप करने के लिए दोषी ठहराया गया।
2. मधेसियों के मुद्दे में 'अनौपचारिक नाकेबंदी के लिए भारत को भी दोषी ठहराया गया था, इससे देश के खिलाफ व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और भारत नेपाल संबंधों में और गिरावट आयी।
3. नेपाल में राजनेताओं ने नेपाली राष्ट्रवाद और भारतीय विरोधीवाद का सफलतापूर्वक शोषण किया।
4. भारत-नेपाल संबंधों में एक और बाधा कालापानी सीमा विवाद से आई है।
5. वर्ष 2019 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा एवं लिपुलेख पर और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सुस्ता क्षेत्र पर अपना दावा जताया जिसने भारत नेपाल सम्बन्ध को और अधिक खराब किया।
6. जबकि भारत-नेपाल सीमा का 98% सीमांकन किया गया था. दो क्षेत्र, सुस्ता और कालापानी का निर्णय अधर में था। वर्ष 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख और सुस्ता (पश्चिम चंपारण जिला, बिहार) के क्षेत्र को नेपाल के क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया।
7. हाल के वर्षों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया है और चीन ने धीरे-धीरे इस स्थान को निवेश, सहायता और ऋण से भर दिया है। चीन नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक प्रमुख भागीदार मानता है और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भव्य योजनाओं के हिस्से के रूप में नेपाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहता है।
8. नेपाल और चीन का बढ़ता सहयोग भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के नेपाल के भेद को कमजोर कर सकता है। दूसरी और चीन नेपाल में रह रहे तिब्बतियों द्वारा किसी भी चीन विरोधी रुख के गठन से बचना चाहता है।
9. आंतरिक सुरक्षा यह भारत के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि भारत-नेपाल सीमा वस्तुतः खुली है जिसका उपयोग भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों द्वारा प्रशिक्षित कैडरों की आपूर्ति, नकली भारतीय मुद्रा आपूर्ति के लिये किया जाता है।
10. विश्वास और नैतिक मतभेद विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण भारत-नेपाल के बीच विश्वास घट-बढ़ गया है। नेपाल में कुछ जातीय समूहों के बीच भारत विरोधी भावना है जो इस धारणा से उत्पन्न होती है कि भारत नेपाल में बहुत अधिक लिप्त है और उनकी राजनीतिक संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करता है।

निष्कर्ष: वर्तमान सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए है। कृषि, रेलवे संबंध और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी है। इनमें बिहार के रक्सौल और कामाद के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा मोतिहारी से नेपाल के अमेलखगंज तक दोनों देशों के बीच आयल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल ही में सहमति बनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो. हम सभी जानते है कि नेपाल-भारत रिश्ते सदियों पुराने है। दोनों देशों में भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक

कारणों से जुड़ी है। नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का वैवाहिक, सांस्कृतिक एवं नृजातीय संबंध रहा है। दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहता है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिये किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह उदाहरण कई मायनों में भारत-नेपाल की नजदीकी को दर्शाता है।भारत नेपाल संबंधों को लेकर के वर्तमान परिदृश्य में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय का सबसे ज्यादा प्रयास यह रहेगा कि नेपाल में लोकतंत्र की जड़े मजबूत हो। क्योंकि चीन अपने साम्यवाद विस्तार की योजना को लगातार नेपाल में बढ़ता जा रहा है। उसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि भारत को नेपाल को यह भरोसा कायम करने में सफल हो सके की नेपाल के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को पूरा करना भारत के साथ निरंतर मैत्री संबंधों को मजबूत करना होगा। इस दिशा में भारत ने भी सकारात्मक प्रयास किए। नेपाल को भी उन प्रयासों के सफल करने में अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में ऐसा लगता है कि दोनों देशों के निकट आने से एशियाई शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बदलाव आएंगे।

संदर्भ:-

1. प्रधानमंत्री ने कहा, सम्मेलन से बुद्ध पर भ्रम दूर करने में मदद मिलेगी", द रिंगिंग नेपाल, 10 मई 2016
2. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/India नेपाल सीमा प्रबंधन 300615.pdf
3. https://www.drittitas.com/hindi/to-the-points/paper2/india-nepal-relatioris
4. https://samparkभारतnepal.com/
5. https://www.indembkathmandu.gov.in/page/about-nepal-bhart-library/
6. https://www.bbc.com/hindi/articles/c4njn7n7pdqo
7. https://in.nepalembassy.gov.np/contact/
8. https://www.ibpbooks.com/bhart-nepal-sambandh-hindi
9. काठमांडू पोस्ट, 19 मई 2021
10. http://www.catchnews.com/india-news
11. "भारत ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह बनाया", काठमांडू पोस्ट, 21 फरवरी 2023
12. Ministry of External Affairs, Government of India. "Visit of Minister for Foreign Affairs of Nepal, H.E Dr. Arzu Rana Deuba to India."Ministry of External Affairs. August 19, 2024, https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/38180/Visit+of+Minister+for+Foreign+Affairs+of+Nepal+HE+Dr+Arzu+Rana+Deuba+to+India (Accessed Octobert 27, 2024).
13. Parshuram Kafle. "दिल्लीमा आरजुलाई प्रधानमन्त्रीहाराहारीकै सम्मान." Naya Patrika. August 20, 2024. https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/147882/2024-08-21 (Accessed October 27,2024)
14. वही.
15. The Kathmandu Post. "Nepal doesn't play one neighbour against the other: Oli." The Kathmandu Post. August 27, 2024, https://kathmandupost.com/national/2024/08/27/nepal-doesn-t-play-one-neighbour-against-the-other-oli (Accessed October 27, 2024).
16. वही
17. Subodh C. Bharti. 2024. "Implications of the LDC Graduation of Nepal." Indian Council of World Affairs. August 19, 2024, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=11681&lid=7109 (Accessed October 27, 2024).
18. Press Trust of India. "Problems with India can be resolved through open dialogue: Nepal PM Oli." The Business Standard. September 7, 2024, https://www.business-standard.com/external-affairs-defence-security/news/problems-with-india-can-be-resolved-through-open-dialogue-nepal-pm-oli-124090700533_1.html (Accessed October 27, 2024).
19. वही.